

Title: Need to strengthen the Rural Banks and grant autonomy to the National Gramin Bank under NABARD. – Laid.

श्री गजेन्द्रसिंह राजूखेड़ी (धार): अध्यक्ष महोदय, देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण अंचलों में 196 ग्रामीण बैंकों की 14500 शाखाएं स्थापित की गयी। देश के 511 जनपदों में ग्रामीण बैंकिंग की सुविधा इन ग्रामीण बैंकों द्वारा मुहैया करायी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बैंकिंग सेवाओं में इन ग्रामीण बैंकों द्वारा अकेले 40 प्रतिशत की भागीदारी की जा रही है। तमाम शासकीय प्राथमिकता की योजनाओं में ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, कृषि ऋण वितरण के साथ-साथ सभी सरकारी गैर सरकारी कर्मियों को वेतन भत्ते इत्यादि जैसे कार्य केवल इन ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता समूहों में 50 फीसदी भागीदारी अकेले ग्रामीण बैंकों की है। गांव में सीमित बैंकिंग संभावनाओं एवं प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकिंग के बावजूद भी लाभ कमाने वाली ग्रामीण बैंकों की संख्या व धनराशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा है कि ग्रामीण बैंक अब घाटे से उबर चुके हैं और शीघ्र ही अपने पांव पर खड़े हो जायेंगे। एक तरफ सरकार इन्हें अपार संभावना वाली बैंक मानती है और वहीं दूसरी तरफ इन बैंकों में अपनी 50 फीसदी की हिस्सेदारी को बेचने का प्रयास भी कर रही है। इस आशय का एक प्रस्ताव भारतीय बैंक संघ को वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि ग्रामीण बैंकों को मजबूत आधार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, जो नाबार्ड के अधीन है, उसे पूर्ण स्वायत्तशाही बैंकिंग संस्थान बनाने का प्रावधान किया जाये।